International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 25-05-2022, Accepted: 11-06-2022, Published: 30-06-2022
Volume 8, Issue 3, 2022, Page No. 137-141

यूपी चुनाव 2022 में योगी सरकार की सफलताः महिला सशक्तीकरण का नया दौर

डॉ सुनीता पारीक
एसोसिएट प्रोफ़ेसर, राजनीति विज्ञान विभाग अदिति कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, भारत

सांराश
यूपी चुनाव का एलान होने के साथ ही सभी राजनीतिक दल अपने अपने मुद्दों के तहत चुनावी दंगल में कूद पड़े। अगर यूपी चुनाव को देखा जाए और नेताओं ने जो वादे किए हैं और जो भाषण दिया उस सारे क्रियाकलाप पर नजर डाली जाए तो एक बात तो साफ साफ से हमारे सामने आती है कि चुनाव के केंद्र में इस बार यूपी में महिलाएं और युवा है। नेता इन्हीं को ध्यान में रखकर वादों की बौछार कर रहे थे और इन्हीं के मुद्दों के इर्द–गिर्द अपने भाषण दे रहे थे। अब जबकि यूपी चुनाव का नतीजा आ चुका है और बीजेपी अपनी जीत का परचम लहरा चुकी है तो कहीं ना कहीं यह सोचना स्वभाविक है कि, जहां सभी पार्टियां महिलाओं और युवाओं को लेकर उनको अपने भाषणों में लुभाने में लगी थी तो बीजेपी में योगी सरकार के नेतृत्व में क्या ऐसा चमत्कार हुआ कि महिला मुद्दों को लेकर दोबारा से योगी सरकार ने चुनाव में बाजी मारी किन्तु क्या ये चुनावी वादे जमीनी स्तर आ पाएंगे? इन महिला सुधारोन्मुखी चुनावी वादों के क्रियान्वयन में किन–किन चुनौतियां का समाना करना पड़ेगा? इसके साथ ही ये सुधार महिला सशक्तीकरण के संवर्धन में किस सीमा तक सफल होगें? इस शोध आलेख में इन सभी प्रश्नों का तथ्यात्मक विश्लेषण किया जायेगा।

मूल शब्दः महिला सशक्तीकरण, उज्ज्वला योजना, निराश्रित पेंशन योजना

प्रस्तावना
किसी भी राज्य में अगर विकास कार्यों की चर्चा की जाए तो वह राजनीतिक दलों द्वारा क्रियान्वित की गई विकास नीतियों से प्रकट होता है, जहां यह जांचा जाता है कि वर्तमान सरकार ने सत्ता संभालने के साथ अपनी विकास रणनीति के द्वारा राज्य, प्रशासन और नागरिकों के जीवन स्तर को बदलने में क्या भूमिका निभाई है, रोजगार के साधन बढ़ाने के लिए क्या रणनीति अपनाई है? महिलाओं के मुद्दे खासकर सुरक्षा मुद्दे को सुलझाने में सरकार की क्या भूमिका रही है? और यूपी में तो जब–जब विकास मुद्दे की बात विभिन्न टीवी चौनलों समाचार पत्रों और चुनावी मुद्दों के कार्यक्रम के द्वारा रखी गई तो ज्यादातर महिलाओं ने योगी के साथ–साथ मोदी का नाम भी लिया जिससे जिससे यह तो साफ–साफ रहे हो गया कि चुनाव भले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का हो लेकिन भाजपा का चेहरा कहीं ना कहीं आज भी मोदी है। जब जब यूपी में योगी सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों की बात हुई तो ज्यादातर महिलाओं ने यह माना कि भाजपा सरकार के आने के बाद काफी विकास कार्य हुए हैं। स्कूल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बने हैं। छात्राओं के लिए कई तरह की योजनाएं शुरू की गई है। फ्लाईओवर और हाईवे का निर्माण कार्य हुआ है। गांव में सड़के और बिजली व्यवस्था ठीक हुई है। लेकिन कई जगह पर ऐसा भी सुनने को मिला कि बिजली की समस्या अभी भी है हाईवे फ्लाईओवर बने तो हैं लेकिन गली मोहल्लों की सड़के आज भी खराब है और कई बार यह भी सुनने में आया की कुछ खास विकास कार्य नहीं हुए। लेकिन कुल मिलाकर हवा का रुख बीजेपी के पक्ष में रहा जिसकी एक खास वजह योगी सरकार के द्वारा महिलाओं के पक्ष में बनाई गई नीतियां और महिलाओं को खासकर ग्रामीण महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई योजनाएं हैं।
महंगाई बना मुद्दारू यह तो हमे मानना पड़ेगा कि जब जब महंगाई में बढ़ोतरी हुई है तब तक महिलाओं का जीवन प्रभावित हुआ है क्योंकि गैस, पेट्रोल, डीजल के साथ–साथ सब्जी तेल व अन्य खाद्य पदार्थ भी महंगे हुए हैं, जिससे एक महिला को घर चलाने में अच्छी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। योगी सरकार ने महिलाओं को राहत पहुंचाने के लिए ऐसे कई प्रभावशाली योजनाएं शुरू की,जिसका नतीजा यूपी चुनाव में हमें साफ दिखाई पड़ा और इसके अलावा युवा पीढ़ी की उभरती हुई महिलाएं जो शिक्षा के द्वारा अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हैं और आत्मनिर्भर बनना चाहती है, उनके लिए योगी सरकार के द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई गई।

महिला सुरक्षा का मुद्दा
महिलाओं की रसोई व्यवस्था के साथ–साथ एक और मुद्दा जो सरकार को चुनाव जिताने में सफल हुआ वह था महिला सुरक्षा व्यवस्था। कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा व्यवस्था के मुद्दे को चुनावी प्रचार में में सभी राजनीतिक दलों के द्वारा खूब भुनाया गया और लगभग सभी महिलाओं ने यह माना कि सुरक्षा व्यवस्था पहले के मुकाबले मजबूत हुई है और उन्हें घर से निकलने में अब डर नही लगता। पुलिस या अन्य हेल्प लाइन नंबर पर शिकायत करते ही तुरंत मदद मिलती है। अमर उजाला द्वारा यूपी चुनाव पर किए गए सर्वे में 982 महिलाओं ने चर्चा में शामिल होकर अपनी बात रखी जिसमें 754 महिलाओं ने यह माना कि पहले के मुकाबले उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है।[1] अमर उजाला के सत्ता के संग्राम ने 45 दिनों में अपने इस सफर को पूरा किया जिसमें गाजियाबाद, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुरा, लखीमपुर, खीरी ,सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद,कन्नौज, इटावा, मैनपुरी, एटा ,फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा,

हाथरस, अलीगढ़, बुलंदशहर, लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, वाराणसी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी ,रायबरेली ,फतेहपुर, चित्रकूट, बांदा ,महोबा, झांसी हमीरपुर ,कानपुर ,उन्नाव ,और नोएडा तक के सफर को तय किया गया जिसमें बारह सौ से ज्यादा महिलाओं ने अपनी बात रखी और मौजूदा हालात से रूबरू कराया।[2]

प्रदेश की साफ सफाई का मुद्दा

उत्तर प्रदेश के चुनावी आकलन के दौरान विकास कार्य, महंगाई और महिला सुरक्षा के अलावा साफ सफाई की व्यवस्था भी महत्वपूर्ण मुद्दा था जिसमें ज्यादातर महिलाओं ने सरकार की तारीफ की और बताया कि अब घर–घर से कूड़ा उठाने की व्यवस्था की गई है जिससे कि पहले के मुकाबले साफ सफाई ठीक से रहती है।

शिक्षा व्यवस्था और रोजगार का मुद्दा

इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जो देश की आधी आबादी को आत्मनिर्भरता के साथ जोड़ने का काम करता है वह है शिक्षा व्यवस्था और रोजगार जिसके लिए महिलाओं ने कहा कि सरकार को और अधिक रोजगार उन्मुख योजनाएं चलानी चाहिए और जहां कहीं पर भी सरकारी नौकरियों में जो खाली जगह है उन्हें भरना चाहिए भर्ती परीक्षाएं समय पर होनी चाहिए और समय–समय पर नौकरी के लिए वैकेंसी भी निकलनी चाहिए ताकि सभी महिलाओं को इसका लाभ मिले।

इस तरह से चुनावी आकलन के दौरान यह पता चला कि जहां कुछ महिलाएं योगी सरकार के पक्ष में थी वही कुछ महिलाएं अखिलेश को अपना विकल्प बता रही थी और कुछ महिलाओं ने प्रियंका गांधी और मायावती का नाम भी लिया लेकिन फिर से चुनावी परिणाम से यह बात स्पष्ट हुई कि कहीं ना कहीं यह योगी सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए की गई योजनाएं ही थी जिसकी वजह से यूपी में बीजेपी दोबारा एक बड़े बहुमत के साथ आई।

नारो की राजनीति

उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में महिला विधायकों का इस बार जीतने का रिकॉर्ड बना, जहां 2017 में यह संख्या 44 विधायकों की थी वहीं इस बार 48 महिला विधायकों ने जीत हासिल की।ङ कांग्रेस ने 'लड़की हूं लड़ सकती हूंश के नारे से अपने यूपी चुनाव के अभियान की शुरुआत की जिसकी चुनावी नतीजे आते आते पूरी तरह से हवा निकल गई। अगर किसी वर्ष में कितनी महिलाएं विधायक बने उसकी बात की जाए तो वर्ष 1989 में महिला विधायकों की सीटें 18 रही

1991 में 10
1992 में 14
1996 में 20
2002 में 26
2007 में 23
2012 में 35
2017 में 44
और 2022 में 48 सीटों पर महिला विधायक थी।[4]

अगर यूपी चुनाव के पिछले तीन विधानसभा चुनाव को इन आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो यह साफ स्पष्ट है कि जिस पार्टी पर महिला मतदाताओं ने अपना भरोसा जताया यूपी में लखनऊ में उसी के सरकार बनी है। यूपी चुनाव में एक नया ट्रेंड जो साफ स्पष्ट दिखाई देता है वह यह है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने अपने मुद्दों को आगे रखा और वोट देने में भी आगे रही। कहीं ना कहीं चाहे शहरी महिलाएं हो या ग्रामीण आंचल में रहने वाली महिलाएं उन्होंने योगी और मोदी के द्वारा यूपी में किए गए योजनाओं को देखते हुए बीजेपी सरकार पर दोबारा भरोसा जताया जिसमें महिला सुरक्षा का मुद्दा और शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा उनकी प्राथमिकता रहा जहां 'एंटी रोमियो दलश के आधार पर मनचलों की हरकतों पर जो लगाम लगी और महिलाओं को पुलिस व अन्य हेल्पलाइन नंबर पर फोन करने पर तुरंत सहायता मिली। इन सब बातों ने यूपी सरकार को जीतने का रास्ता दोबारा से खोला। चाहे वह महंगाई का मुद्दा रहा हो, चाहे विकास कार्यों का, महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, या चाहे तीन तलाक का मुद्दा, कहीं ना कहीं महिलाओं के द्वारा किए गए कार्यों के द्वारा यूपी सरकार को जीत हासिल हुई। हालांकि प्रियंका गांधी के नारे 'लड़की हूं लड़ सकती हूं' से काफी महिलाएं प्रभावित हुई लेकिन भाजपा सरकार का' नारी सुरक्षाश का एजेंडा इस नारे पर भारी पड़ा। इस चुनाव के द्वारा महिलाओं ने यह बताया कि महिलाएं अपनी स्वयं की सोच पर मतदान कर रही है और उसी पार्टी को अपनी प्राथमिकता बना रही है जो उनके विकास की बात करता है।

मुख्यमंत्री आदित्य नाथ योगी के द्वारा यूपी में चलाई गई महिला सशक्तिकरण की योजनाएं

उज्जवला योजना

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्य की गरीब परिवार की महिलाओं के लिए और उन्हें मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन की सुविधा प्रदान करने के लिए 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से इस योजना की शुरुआत की गई। यूपी में बीजेपी सरकार की सफल योजनाओं के बाद की जाए तो उज्जवला योजना उसमें से एक है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को लकड़ी के कोयले के धुए से मुक्त कराना है। योजना के तहत केंद्र सरकार तेल कंपनियों को हर एक कनेक्शन पर 1600 की सब्सिडी देती है जिन परिवारों के नाम बीपीएल कार्ड है वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं इस योजना का लाभ केवल महिलाए ही उठा सकती हैं। आवेदक महिला की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए

साथ ही एक ही घर में इस योजना के तहत कोई अन्य एलपीजी कनेक्शन भी नहीं होना चाहिए।[6] उज्जवला योजना का उद्देश्य यह था कि देश में कई ऐसे गरीब परिवार की महिलाएं हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से वह काफी दिक्कतों का सामना कर रही है।

यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए एक सफल योजना साबित हुई जिसने कमजोर गृहणियों को रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया। 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में उज्ज्वला योजना का लाभ एक करोड़ और लाभार्थियों तक पहुंचाने की घोषणा की है। उज्जवला योजना के पहले चरण में यूपी के 50 से ज्यादा जिलों में करीब 21 लाख घरों को इससे जोड़ने का लक्ष्य रखा गया।[7] साथ ही साथ यह योजना गोबर से बायोगैस बनाने को प्रोत्साहन देती है जिससे गांव में स्वच्छता भी आई और ऐसे पशु जो डेयरी सेक्टर के लिए उपयोगी नहीं थे, वह भी कमाई का जरिया बने। उज्जवला योजना की पहले चरण की शुरुआत यूपी के बलिया से हुई थी, वही उज्जवला 2.0 की शुरुआत यूपी के महोबा से की गई जिसमें जहां योजना के पहले चरण में 8 करोड़ गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी परिवार की बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया, वही योजना के दूसरे चरण में सरकार का राज्य में 20 लाख लाभार्थियों को नए एलपीजी कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया। योजना 2.0 की घोषणा 10 अगस्त 2021 को वित्तीय वर्ष 2021–22 में की गई ।[8] दूसरे चरण में गैस कनेक्शन पाने के लिए प्रवासी मजदूरों को भी बड़ी राहत दी गई, उनके लिए अब यह व्यवस्था की गई कि वह बिना स्थाई पते के भी नया कनेक्शन ले सकेंगे और प्रवासी मजदूरों को गरीबी रेखा का प्रमाण देने के लिए पहले जहां राशन कार्ड की जरूरत पड़ती थी वहीं अब उन्हें बड़ी राहत दी गई और पते के प्रमाण के तौर पर अब प्रवासी मजदूर सिर्फ एक कागज पर लिख कर दे सकते हैं कि वह किस पते पर रहते हैं।

मुख्यमंत्री महिला सामर्थ्य योजना और मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना

उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को बनाए रखने के लिए और उनके बढ़ते कदमों को और आगे बढ़ाने के लिए और महिला सशक्तिकरण को वास्तविक रूप से नई दिशा देने के लिए तथा उन्हें रोजगार की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए दो बड़ी योजनाओं 'मुख्यमंत्री महिला सामर्थ्य योजना' एवं 'मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजनाश की शुरुआत 22 फरवरी 2021 में की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं का कल्याण तथा सशक्तिकरण करना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण देना है, जिससे कि वह अपने उद्योगों को और बेहतर बना सके और आत्मनिर्भर बन सके। इस योजना के पहले चरण में 200 विकास खंडों में महिला सामान्य केंद्र विकसित किए जाएंगे और प्रदेश के महिलाओं को रोजगार के लिए प्रेरित किया जाएगा।[9] मुख्यमंत्री महिला समृद्धि योजना से महिला व्यापारियों को सीधा लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है तथा लघु कुटीर उद्योग धंधों से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का और उनके जीवन स्तर को सुधारने की योजना तय की गई ताकि महिलाएं रोजगार के द्वारा स्वाबलंबन की ओर बढ़े।[10] बीजेपी सरकार की ऐसी योजनाओं के द्वारा ही महिलाओं ने अपना भरोसा सरकार पर जताया और चुनाव में जीत हासिल करवाई।

बैंक सखी योजना

बैंक सखी योजना के तहत यूपी की महिलाओं को रोजगार दिलाने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए यूपी सरकार ने इस स्कीम के तहत चयनित महिलाओं को हर माह वेतन के रूप में ₹4000 प्रदान करने की योजना शुरू की।[11] इसके अतिरिक्त हर महिला को डिजिटल डिवाइस खरीदने के लिए ₹50000 अतिरिक्त रकम देने का प्रावधान रखा गया, इस योजना की शुरुआत 22 मई 2020 को की गई थी। यह योजना खासतौर पर बैंकों के लिए हैं। बैंक सखी योजना के द्वारा कोरोना काल में काफी मदद मिली। बैंकों में भीड़ भाड़ को देखते हुए और महिलाओं को आसानी से बैंकों के द्वारा आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए इसका लक्ष्य रखा गया। बैंक सखी योजना से जोड़ने का जो प्रावधान था उसने भी महिलाओं को इस योजना का लाभ पहुंचाने में मदद की जिसने अंततः बीजेपी को चुनावी जीत के लक्ष्य तक पहुंचाया। इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को सिर्फ गूगल प्ले स्टोर पर जाकर बीसी सखी ऐप को डाउनलोड करने के बाद उस ऐप में अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करने के बाद सिर्फ एक जनरल प्रोफाइल के बटन पर क्लिक करना था और अपनी जानकारी दर्ज कर आते ही सबमिट के बटन पर क्लिक करने के साथ उस महिला की आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो जाती थी, और कहीं ना कहीं बैंक सखी योजना के द्वारा महिलाओं को जो फायदा पहुंचा उसने दोबारा बीजेपी को यूपी इलेक्शन जीतने में मदद की।

मुखबिर योजना

जैसा कि इस योजना के माध्यम के इस के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यह सूचना देने वाले की बात कर रही है और इस योजना के द्वारा कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और महिलाओं के जन्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सीएम योगी ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं को एक और कदम आगे बढ़ाते हुए मुखबिर योजना का प्रारंभ किया, जिसके लिए 181 हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया जिसके तहत 64 रेस्क्यू वैन भी तैयार की गई इसके साथ ही साथ इसी योजना के अंतर्गत आशा ज्योति केंद्र को 11 से बढ़ाकर 75 जिलों में आवंटित किया गया और इस योजना से कन्या भ्रूण हत्या की के द्वारा उसे रोककर कन्याओं को बचाने का प्रयास किया गया वहीं घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को भी इस योजना के तहत मदद मांगने का प्रावधान रखा गया, इस योजना के द्वारा अगर कोई भी कन्या भ्रूण हत्या की सूचना देगा तो उसे 10000 से 200000 तक के इनाम की व्यवस्था की गई।[12]

निराश्रित पेंशन योजना

इसके द्वारा उन महिलाओं को जो कि किसी ना किसी पर आश्रित होकर जीवन गुजारने को मजबूर है उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की बात की गई प्रदेश के सभी विधवा महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत इसके शुरुआती

चरण में ₹500 की आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध करवाने की बात तय हुई । दिसंबर 2021 में योगी सरकार ने निराश्रित महिलाओं और वृद्धों,दिव्यांग जनों को अब हर माह ₹500 की जगह ₹1000 पेंशन देने की बात कही साथ ही श्रमिकों को अगले 4 महीने तक ₹500 और कुष्ठ रोगियों को हर महीने ₹3000 पेंशन के रूप में देने की बात यही गई पहले यह ₹300 थी फिर योगी सरकार ने से ₹500 किया जिसे अब बढ़ाकर ₹1000 किया जाएगा। पेंशन प्राप्त करने वाली निराश्रित महिलाओं की यह संख्या पहले जहां 17 लाख 31हजार थी वही अब तीस लाख चौंतीस हजार महिलाओं को पेंशन दी जा रही हैं। [1]ङसाथ ही साथ योजना के तहत महिला के पति के देहांत के बाद पुनर्विवाह करने पर दंपती को दिए जाने वाले पुरस्कार राशि को ₹11000 से बढ़ाकर ₹51000 करने और दहेज पीड़ित महिलाओं को हर माह ₹500 देने की बात है तथा दहेज पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता लेने की व्यवस्था है।

भाग्य लक्ष्मी योजना

प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या और लिंग अनुपात को रोक लगाने के लिए योगी सरकार ने भाग्यलक्ष्मी योजना की शुरुआत की इस योजना के द्वारा बेटी के जन्म पर माता–पिता को आर्थिक मदद देने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री द्वारा इस योजना को चलाने के लिए प्रदेश की हर एक गरीब परिवार में बेटी के जन्म पर पचास हजार रुपए का एक बॉन्ड देने की बात है तथा बेटी के कक्षा 6 में पहुंचने पर ₹3000 कक्षा आठ में पहुंचने पर ₹5000 कक्षा 10 में पहुंचने पर ₹7000 तथा कक्षा 12 में पहुंचने पर ₹8000 देने की बात है। बेटी के जन्म पर जो पचास हजार रुपए का बॉन्ड मिलता है वह उसके इक्कीस की होने पर मयोचोर होकर दो लाख रुपए हो जाता है। साथ ही साथ बेटी के पालन पोषण के लिए जन्म के समय मां को अलग से इक्यावन सो रुपए मिलते हैं।[14] इस योजना का लाभ केवल गरीबी रेखा से नीचे परिवार की बेटियों को ही मिलेगा जिसमें परिवार की आय प्रतिवर्ष दो लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ इस योजना का लाभ उन्हीं बेटियों को मिलेगा जिनका जन्म 2006 के बाद हुआ है और बेटी के जन्म के एक महीने के अंदर आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकरण होना आवश्यक है। साथ ही साथ बेटी की शिक्षा सरकारी स्कूल में होनी चाहिए और बेटी की शादी अठारह साल से पहले नहीं होनी चाहिए। भाग्य लक्ष्मी योजना के द्वारा गरीब परिवार की बेटी को पढ़ने और बढ़ने का पूरा अवसर दिया गया है।

मिशन शक्ति योजना

योगी सरकार के द्वारा यूपी में महिला अपराध पर लगाम लगाने के लिए मिशन शक्ति योजना की शुरुआत अक्टूबर 2020 में की गई जिसका लक्ष्य महिलाओं के लिए किए जाने वाले अपराधों में कमी करना था और एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाना था।[15] साथ ही मिशन शक्ति अभियान को एक ऑपरेशन के रूप में संचालित करने की योजना तय की गई ताकि महिलाएं प्रदेश में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें और कहीं ना कहीं मिशन शक्ति अभियान के द्वारा सकारात्मक परिणाम भी सामने आए और महिलाओं में अपने अधिकारों को लेकर जागरूकता बढ़ी साथ ही साथ महिलाओं के द्वारा इस योजना को महिला सुरक्षा की दिशा में एक अच्छा कदम मानते हुए स्वीकार किया गया और महिला अपराधों पर लगाम लगाई गई मिशन शक्ति योजना के तीसरे चरण के तहत मुख्यमंत्री योगी ने निराश्रित महिला पेंशन योजना की शुरुआत की थी जिसमें महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा देने की योजना तय की गई।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के उपरांत सीएम योगी ने महिलाओं को यह भरोसा दिलाया कि प्रदेश में आधी आबादी के लिए बहुत सारे काम किए गए हैं और अभी बहुत सारे करने हैं। घर–घर में महिलाओं के लिए अकाउंट खुला, पोषाहार की व्यवस्था की गई और सीएम योगी ने महिलाओं के लिए द्वारा चलाई गई सभी योजनाओं पर उन्हें लागू करने का बात कही और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिसंबर 2021 को स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से मुलाकात की और 1,60 लाख महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए एक हजार करोड़ ऑनलाइन ट्रांसफर किए और इसके अलावा प्रयागराज में आयोजित महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में 2021 टेक होम राशन प्लांट का भी शिलान्यास किया।[16] कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा मुद्दे को और महिलाओं के लिए उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार उन्मुखी कार्यक्रमों को शुरू करना योगी सरकार को दोबारा से प्रदेश में जीत हासिल करने में एक कामयाब कदम बना योगी सरकार के द्वारा अधिकारियों को बराबर यह निर्देश दिए गए थे कि कहीं पर भी अगर महिलाओं के साथ कोई भी आपराधिक घटना हो तो उसे संवेदनशीलता के साथ लिया जाए और साथ ही साथ ऐसी घटनाओं के होने पर तुरंत कार्रवाई की जाए मिशन शक्ति योजना के द्वारा महिलाओं और लड़कियों को जागरूक बनाया गया उन्हें स्वावलंबी बनाया गया इसके अलावा महिलाओं के प्रति हिंसात्मक व्यवहार करने वाले लोगों की पहचान कर उन्हें दंडित किया गया और जागरूक अभियान और कार्यक्रम चलाकर मनचलों के खिलाफ मिशन शक्ति अभियान को सफल बनाया गया ।[17]

शक्ति अभियान के द्वारा महिलाओं के साथ अपराध करने वाले व्यक्ति का अगर कोर्ट में दोष सिद्ध हो जाए तो सभी चौराहों पर उसकी फोटो लगवाना मनचलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना उन्हें पकड़ना जेल भेजना और सभी पुलिस थानों में महिलाओं के लिए एक अलग अलग से हेल्प डेस्क की व्यवस्था करना जहां महिला अधिकारी और सिपाही तैनात रहे इन्हीं सभी बातों ने महिलाओं के अंदर एक नई शक्ति का दम भरा और महिलाओं ने अपने फायदे को देखते हुए अपनी सुरक्षा और अपनी आत्मनिर्भरता को इस चुनाव का महत्वपूर्ण मुद्दा बनाते हुए बीजेपी को जीत हासिल करवाई आने वाले समय में बीजेपी से अपेक्षा है कि वह प्रदेश में ऐसी कई योजनाओं को बढ़ावा देगी जिससे कि महिलाएं मजबूत बने तथा साथ ही साथ प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों को भी पता लगे कि महिलाओं को अनदेखा करना उन्हें भारी पड़ सकता है और महिला उन्मुखी कार्यक्रमों को सरकार के द्वारा और अधिक बढ़ावा दिया जाएगा इसी बात की अपेक्षा है।

प्रदेश में बीजेपी की जीत महिला सशक्तिकरण की जीत है जिसके तहत महिलाओं को स्नातक स्तर तक निशुल्क शिक्षा प्रदान करना उज्जवला योजना के द्वारा एक करोड़ 67 लाख मातृ शक्तियों को मुफ्त गैस कनेक्शन देना, सीएम कन्या

सुमंगल योजना से नौ लाख छ्तीस हजार बेटियों को फायदा पहुंचाना मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 1.52 लाख से अधिक निर्धन कन्याओं का विवाह करवाना प्रदेश के सभी 1535 थानों में पहली बार महिला डेस्क की स्थापना करना और महिलाओं को तुरंत न्याय मिल सके इसके लिए 218 नए फास्ट ट्रेक कोर्ट की स्थापना करना। करीब 56000 महिलाओं को बैकिंग सखी के रूप में कार्य करना तथा 1000000 स्वयं सहायता समूह के माध्यम के द्वारा एक रोड महिलाओं को रोजगार देना यह सब योगी सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए गए वह कदम रहे जिन्होंने सभी नारो और भाषणों से ऊपर जाकर सिर्फ महिला सशक्तिकरण की बात की। केवल अपने भाषणों के द्वारा ही नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप से महिला सुरक्षा और महिला रोजगार को अपना चुनावी मुद्दा बनाया जिसने बीजेपी का प्रदेश में जीत का परचम फिर से लहराया।

संदर्भ सूची

1. अमर उजाला, यूपी के 45 जिलों से ग्राउंड रिपोर्टः चुनावी मुद्दे क्या है? योगी, मोदी और अखिलेश के बारे में क्या सोचती है, प्रियंका का कितना असर? हिमांशु मिश्रा यूपी इलेक्शन 2022 ग्राउंड रिपोर्ट यूपी 45 डिस्ट्रिक्ट वूमेन इलेक्शन इश्यूः अपडेटेड, सैटरडे 8 जनवरी 2022
2. ibid
3. यूपी इलेक्शनः यूपी में आधी आबादी ने बनाया रिकॉर्डः अब तक सबसे ज्यादा 41 महिलाएं बनी विधायक, बीजेपी में सबसे ज्यादा, टीवी 9 हिन्दी, अपडेटेड ऑन फ्राइडे 11 मार्च 2022
4. ibid
5. क्या है? यूपी की महिलाओं का चुनावी मूड, किन मुद्दो पर की वोटिंग? हिमा अग्रवाल, वेबदुनिया हिंदी अपडेटेड, 15 फरवरी 2022
6. उज्जवला योजनाः फ्री रसोई गैस सिलेंडर के लिए उठाए इस सरकारी योजना का लाभ, फायदे में रहेंगे आप, बिजनेस डेस्क अमर उजाला, न्यू दिल्ली एक्सेस्ड ऑन 18 सितंबर 2021.
7. पीएम उज्जवला स्कीम 2.0 गैस कनेक्शन के लिए एड्रेस प्रूफ जरूरी नहीं सेल्फ–डिक्लेरेशन ही पर्याप्त, आज तक. इन, नई दिल्ली 10 अगस्त 2021
8. यूपी में आज से शुरू हो गई उज्वला योजना 2.0, बीस लाख नए एलपीजी कनेक्शन देगी योगी सरकार, काजल कुमारी, इंडिया.काम 25 अगस्त 2021.
9. पीएम मोदी योजनाः यूपी महिला सामर्थ्य योजना 2022, पीएम मोदी योजना. इन अपडेटेड 18 फरवरी 2022, रीना शर्मा
10. महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए योगी सरकार ने की योजनाओं की शुरूआत स्मार्ट न्यूज़ टीम, अपडेटेड, 24 फरवरी 2021
11. बैंक सखी योजनाः यूपी सरकार की इस योजना में महिलाओं को हर माह मिलेंगे ₹4000, पत्रिका, 14 जुलाई 2021
12. उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए सीएम योगी की पांच योजनाएं, प्रतिमा, हिंदी गुड रिटर्न्स.इन, 19 फरवरी 2018
13. इस राज्य में जरूरतमंदों की पेंशन हुई डबल, सीएम ने किया ऐलान जाने हर महीने कितनी राशि मिलेगी, ज़ी बिजनेस हिंदी, अपडेटेड 16 दिसंबर 2021
14. भाग्य लक्ष्मी योजनाः बेटी के जन्म पर यूपी सरकार देती है पचास हजार रूपए,पढ़ाई के लिए भी अलग से मिलते हैं पैसे, एबीपी गंगा, अपडेटेड 21 नवंबर 2021
15. क्या है योगी आदित्यनाथ का मिशन शक्ति अभियान? जानिए उद्देश्य और खास बातें, नवभारत टाइम्स डॉट कॉम, अपडेटेड 6 सितंबर 2021
16. प्रयागराज महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में पीएम मोदी का संबोधन, जानिए बड़ी बाते, नई दुनिया. कॉम, 21 दिसम्बर 2021
17. Opcit, क्या है योगी आदित्यनाथ का मिशन शक्ति अभियान नवभारत टाइम्स डॉट कॉम, अपडेटेड 6 सितंबर 2021